



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21—अगस्त 27, 2010 (श्रावण 30, 1932)  
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21—AUGUST 27, 2010 (SRAVANA 30, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ सं.	विषय	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1247	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	765	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1391	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	2161
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	7233
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	569
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
'ART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	1247	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
'ART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	765	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
'ART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
'ART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1391	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	2161
'ART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
'ART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
'ART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	7233
'ART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	569
'ART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

Folios not received.

## भाग I — खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. 1/6/2008-वि.सा.प्र. (हि.वि.पु.)--विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग (विधि साहित्य प्रकाशन) के संकल्प सं. ई.-13016/3/76-वि.सा.प्र. (हि.वि.पु.) तारीख 4 मई, 1976 के पैरा 3 में :--

(क) उपपैरा (I) के खंड (i) में "प्रथम पुरस्कार 25,000/- रुपये" से आरंभ होने वाले और "50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) से अधिक नहीं होगी" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों से समाप्त होने वाला भाग के स्थान पर "प्रथम पुरस्कार 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) का, द्वितीय पुरस्कार 30,000/- रुपये (तीस हजार रुपये) का, तृतीय पुरस्कार 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये) का होगा। मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्रत्येक ग्रुप में किसी भी प्रवर्ग में एक से अधिक पुरस्कार दिए जा सकते हैं, किन्तु उस ग्रुप में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल रकम 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक नहीं होगी" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपपैरा (IV) के खंड (ii) में "25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये)" अंक, शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

एस. आर. ढलेटा

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 1/1/2010-सी.टी.-II--भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 05.05.2010 के समसंख्यक संकल्प द्वारा गठित कपास सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित को तत्काल प्रभाव से सदस्य के रूप में शामिल करने का अनुमोदन किया है :--

(क) श्री एम. अशोकन, पुरानी सं. 19,  
नई सं. 41, बाबू मुदाली  
स्ट्रीट, वेल्लाला तेइनामपेट,  
चेन्नई-600086

(ख) श्री थिरूगननाम  
2, वनदाइमन कोइल स्ट्रीट,  
पदीकुप्पम, नेरकुप्पम,  
चैन्नई-600107

2. दिनांक 05.05.2010 की संकल्प सं. 1/1/2010-सी.टी.-II उपर्युक्त सीमा तक संशोधित हो गया है।
3. पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य दिनांक 04.05.2012 तक बोर्ड में बने रहेंगे।
4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाए।
5. यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनीता पुरी  
अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय  
विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. 1(17)/एसआईसीडीपी/क्लस्टर/टीएम/2006--केन्द्र सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम/क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के दिशा निर्देशों में संशोधनों का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 303.63 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से कार्यान्वित की जाती रहेगी। योजना का उद्देश्य सॉफ्ट इंटरवेंशन (तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, एक्सपोजर दौरों, बाजार विकास, विश्वास निर्माण, आदि), हार्ड इंटरवेंशन (परीक्षण डिजाइन केन्द्र, उत्पादन केन्द्र, एफ्ल्युएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, कच्चा माल बैंक/बिक्री केन्द्र, उत्पाद प्रदर्शन केन्द्र, सूचना केन्द्र आदि हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों, की स्थापना) तथा अवस्थापना विकास (भूमि का विकास, जल आपूर्ति की व्यवस्था, निकासी, विद्युत वितरण, सामान्य कैपिटल उपयोग हेतु ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों, सड़कों का निर्माण, प्राथमिक उपचार केन्द्र, कैंटीन आदि जैसी सामान्य सुविधाओं, आदि) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है।

2. योजना का ब्यौरा तथा संशोधित दिशा-निर्देश विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय की वेबसाइट अर्थात् [www.dcmsme.gov.in](http://www.dcmsme.gov.in) पर उपलब्ध है।

हुकुम सिंह मीणा  
संयुक्त विकास आयुक्त

नई दिल्ली-110108, दिनांक 10 अगस्त 2010

सं. 81(1)/डीपीआर/आईसीटी/2008/आईटी--केन्द्र सरकार ने कुल 105.00 करोड़ रुपये के बजट (जिसमें 47.70 करोड़ रुपये का भारत सरकार का अंशदान शामिल है) से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के तहत 'एमएसएमई क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का संवर्धन' नाम से एक योजना अनुमोदित की है, जिसे 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रभावी एमएसएमई क्लस्टरों को अपने उत्पादन एवं व्यवसाय प्रक्रियाओं में आईसीटी संसाधनों और अनुप्रयोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करना और सहायता करना है ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाया जा सके।

योजना का ब्यौरा और दिशा-निर्देशिका विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट यानि [www.dcmsme.gov.in](http://www.dcmsme.gov.in) पर उपलब्ध है।

अभय बाकरे  
संयुक्त विकास आयुक्त

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

New Delhi, the 20th July 2010

No. 1/6/2008-VSP (HLB)—In the Resolution No. E-13016/3/76-VSP (HLB), dated the 4th May, 1976 of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department (Vidhi Sahitya Prakashan), in paragraph 3,—

- (a) in sub-paragraph (I), in clause (i), for the portion beginning with the words, letters, figures and brackets "The first prize shall be" and ending with the words, letters and figures "not exceed Rs. 50,000/-" the words, letters, figures and brackets "The first prize shall be of an amount of Rs. 50,000/- (rupees fifty thousand), the second of an amount of Rs. 30,000/- (rupees thirty thousand), the third of an amount of Rs. 20,000/- (rupees twenty thousand). On the recommendations of Evaluation Committee more than one prize of any category may be awarded in each group whatsoever but the total amount of the prizes awarded in that group shall not exceed Rs. 1,00,000/-" shall be substituted;
- (b) in sub-paragraph (IV), in clause (ii), for the words, letters, figures and brackets "one prize of Rs. 25,000/- (rupees twenty-five thousand)" the words, letters, figures and brackets "Rs. 50,000/- (rupees fifty thousand)" shall be substituted.

S. R. DHALETA  
Jt. Secy. & Legislative Counsel

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 27th July 2010

No. 1/1/2010-CT-II—The Competent Authority in the Government of India has approved the inclusion of the following:—

- (a) Shri M. Asokan, Old No. 19,  
New No. 41, Babu Mudali  
St., Vellala Teynampet,  
Chennai-600086.
- (b) Shri Thirugnanam,  
2, Vandiamman Koil Street,  
Padikuppam, Nerkuppam,  
Chennai-600107

as members of the Cotton Advisory Board, constituted vide Resolution of even No. Dated 05/05/2010, with immediate effect.

2. The Resolution No. 1/1/2010-CT-II dated 05.05.2010 stands modified to the extent stated above.
3. The Members of the reconstituted Board will serve on the Board upto 04.05.2012.
4. Ordered that the copy of this Resolution be communicated to the concerned.
5. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

ANITA PURI  
Under Secy.

## MINISTRY OF MICRO, SMALL &amp; MEDIUM ENTERPRISES

## OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (MICRO, SMALL &amp; MEDIUM ENTERPRISES)

New Delhi, the 10th February 2010

No. 1(17)/SICDP/Cluster/TM/2006—The Central Government has approved Modifications in the Guidelines of Micro & Small Enterprises—Cluster Development Programme (MSE-CDP). The scheme will continue to be implemented at a total outlay of Rs. 303.63 crore during 11th Five Year Plan. The scheme aims at enhancing the competitiveness and productivity of Micro & Small Enterprises by undertaking soft interventions (Technical assistance, capacity building, exposure visits, market development, trust building, etc.), Hard Intervention [setting up of Common Facility Centers (CFCs) for Testing, Design Centre, Production Centre, Effluent Treatment Plant, Training Centre, R&D Centre, Raw Material Bank/Sales Depot, Product Display Centre, Information Centre, etc] and Infrastructure Development (Development of land, provision of water supply, drainage, power distribution, non-conventional sources of Energy for common captive use, construction of roads, common facilities such as First Aid Centre, Canteen, etc).

2. The details of the scheme and modified guidelines are available on the official website of the office of DC(MSME) i.e. [www.dcsmse.gov.in](http://www.dcsmse.gov.in).

HUKUM SINGH MEENA  
Jt. Development Commissioner

New Delhi-110108, the 10th August 2010

No. 81(1)/DPR/ICT/2008/IT/68—The Central Government has approved a scheme titled, "Promotion of Information and Communication Technology (ICT) in MSME sector" under the National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) with a total budget of ₹ 105.00 crore (including Government of India contribution of ₹ 47.70 crore) to be implemented during the 11th Plan period. The main objective of the scheme is to encourage and assist the potential MSME clusters to adopt ICT tools and applications in their production & business processes, with a view to improving their productivity and competitiveness in national and international markets.

The details of the scheme and guidelines are available on the official website of the office of DC (MSME) i.e. [www.dcsmse.gov.in](http://www.dcsmse.gov.in).

ABHAY BAKRE  
Jt. Development Commissioner